राष्ट्रपति के 2021 के अभिभाषण के मुख्य अंश

भारत के राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद ने 29 जनवरी, 2021 को संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित किया। उन्होंने अपने अभिभाषण में सरकार की प्रमुख नीतिगत उपलब्धियों को रेखांकित किया। अभिभाषण के मुख्य अंश निम्नलिखित हैं:

अर्थव्यवस्था और वित्त

- सरकार बैंकिंग प्रणाली को सशक्त करने के लिए छोटे बैंकों का विलय कर रही है और बड़े और मजबूत बैंक बना रही है।
- जन धन खातों, आधार और मोबाइल के इस्तेमाल के कारण 1.8 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के जरिए लाभार्थियों के बैंक खातों में 2014 से 13 लाख करोड़ रुपए से अधिक हस्तांतरित हुए हैं।
- अप्रैल और अगस्त 2020 के बीच भारत में 36 बिलियन डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किया गया है।
- ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग में सुधार हुआ है।

स्वास्थ्य और कोविड-19

- भारत ने 2,200 लैब्स का नेटवर्क विकसित करके, तथा घरेलू स्तर पर हजारों वेंटिलेटर्स, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट (पीपीई) किट्स, तथा टेस्ट किट्स बनाकर महामारी से मुकाबला किया है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा कोविड-19 वैक्सीनेशन कार्यक्रम भी चला रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत दोनों वैक्सीन घरेलू स्तर पर बनाई गई हैं। कोविड-19 के नए मामलों में लगातार गिरावट आ रही है और रिकवरी के मामलों की संख्या बढ़ रही है।
- आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 1.5 लाख गरीब लोगों को पांच लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिला है और 30,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है।
- सरकार ने लॉकडाउन के दौरान प्रवासियों और मजदूरों के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन्स चलाईं ताकि वे अपने गृह राज्यों को लौट सकें।
- प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि योजना के अंतर्गत 7,000 जनौषधि केंद्र स्थापित किए गए हैं ताकि गरीब लोगों को सस्ती दवाएं मिल सकें।
- 2014 से मेडिकल कॉलेजों की संख्या 387 से बढ़कर 562 हो गई है। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत 22 नए एम्स को मंजूरी दी गई है।
- पुरानी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के स्थान पर नेशनल मेडिकल कमीशन की स्थापना की गई है।

कृषि और खाद्य वितरण

- तीन कृषि बिल: (i) किसान उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) बिल, 2020, (ii) मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं पर किसान (सशक्तीकरण और संरक्षण) समझौता बिल, 2020 और (iii) अनिवार्य वस्तुएं (संशोधन) बिल, 2020 पारित किए गए।
- एमएसपी को उत्पादन लागत का कम से कम डेढ़ गुना बढ़ा दिया गया।
- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत छोटे और सीमांत किसानों के खातों में आय समर्थन के रूप में 1.13 लाख करोड़ रुपए हस्तांतरित किए गए हैं।
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत पिछले पांच वर्षों में बीमाकृत किसानों को मुआवजा देने के लिए 90,000 करोड़ रुपए चुकाए गए हैं।
- लॉकडाउन के दौरान आठ महीनों में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत 80 करोड़ लोगों को 5 किलो मुफ्त अनाज दिया गया जोकि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट, 2013 की पात्रता के अतिरिक्त है। इसके अलावा वन

श्रुति गुप्ता shruti@prsindia.org
प्राची कौर prachi@prsindia.org

29 जनवरी, 2021

नेशन, वन राशन कार्ड की मदद से अपने घरों से दूर प्रवासी मजदूरों और श्रमिकों को देश भर में अपनी हकदारियां मिलीं।

- कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार के लिए एक लाख करोड़ रुपए का कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाया गया है। इसी प्रकार डेयरी क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए 15,000 करोड़ रुपए का पशुपालन इंफ्रास्ट्रक्चर विकास फंड भी बनाया गया है।

मैन्यूफैक्चरिंग और रोजगार सृजन

- चार श्रम संहिताएं पारित की गईं जिनमें 29 केंद्रीय श्रम कानून सम्मिलित किए गए हैं।
- कंपनी एक्ट, 2013 के कई प्रावधानों को गैर आपराधिक बनाया गया है।
- 10 मैन्यूफैक्चरिंग क्षेत्रों में 1.5 लाख करोड़ मूल्य की प्रोडक्शन लिंक्ड इनसेंटिव स्कीम को लागू किया गया है।
- कोविड-19 महामारी के दौरान लघु स्तर के उद्योगों को लाभ पहुंचाने के लिए अनेक कदम उठाए गए, जैसे तीन लाख करोड़ रुपए की इमरेंजसी क्रेडिट गारंटी योजना, मुश्किल में फंसे एमएसएमईज़ के लिए 20,000 करोड़ रुपए की विशेष योजना और फंड ऑफ फंड्स।
- कोविड-19 महामारी के दौरान छह राज्यों में गरीब कल्याण रोजगार अभियान शुरू किया गया और अपने गांवों में लौटने वाले प्रवासी मजदूरों को 50 करोड़ मानव दिवस के बराबर रोजगार मिला।
- नौकरियों के लिए रिक्रूटमेंट प्रक्रिया को आसान बनाने और स्ट्रीमलाइन करने के लिए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की स्थापना की गई।

रक्षा और आंतरिक मामले

- जून 2020 में भारत चीन संघर्ष के कारण गलवान घाटी में 20 सैनिकों की जान गई। इसके बाद से भारत की संप्रभुता की रक्षा के लिए एलएसी पर अतिरिक्त बलों की तैनाती की गई है।
- सशस्त्र बलों की क्षमता बढ़ाने के लिए आधुनिक रक्षा उपकरणों की खरीद की गई है। 48,000 करोड़ रुपए के मूल्य वाले 83 देसी लड़ाकू विमानों तेजस के निर्माण का ऑर्डर दे दिया गया है।
- भारत रक्षा उपकरणों के निर्यात के क्षेत्र में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहा है। अनेक अत्याधुनिक हथियार, जैसे क्विक रिएक्शन मिसाइल, टैंक और स्वदेशी राइफल देश में ही बन रहे हैं।
- नक्सली हिंसा की घटनाओं में कमी आई है और नक्सल प्रभावित क्षेत्र का दायरा सिमट रहा है। पूर्वोत्तर में हिंसक उग्रवादी घटनाओं में भी कमी आई है।

इंफ्रास्ट्रक्चर और परिवहन

- सभी क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉजेक्ट्स को विकसित करने के लिए 110 लाख करोड़ रुपए मूल्य की नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन को लागू किया गया है।
- चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर तक सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल, अटल टनल और चार धाम रोड प्रॉजेक्ट जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉजेक्ट्स को लागू किया गया है।
- भारतमाला परियोजना के अंतर्गत छह नए एक्सप्रेसवे और 18 एक्सेस कंट्रोल्ड रोड कॉरिडोर्स का निर्माण चालू है।

शहरी और ग्रामीण विकास

- प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 2014 से ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब परिवारों के लिए दो करोड़ मकान बनाए गए हैं। शहरी क्षेत्रों में गरीबों के लिए एक करोड़ से अधिक मकानों को मंजूरी दी गई है, जिनमें से 40 लाख मकानों का निर्माण पूरा हो चुका है।
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में 6.42 लाख किलोमीटर सड़क का निर्माण पूरा कर लिया गया है। इस योजना के तीसरे चरण में 1.25 लाख किलोमीटर रास्तों को अपग्रेड किया जाएगा।

ऊर्जा

- 2014 से भारत की अक्षय ऊर्जा क्षमता 2.5 गुना बढ़ चुकी है और सौर ऊर्जा क्षमता 13 गुना। इसके अतिरिक्त भारत के ऊर्जा उत्पादन में एक चौथाई हिस्सा अक्षय ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त होता है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में बिजलीकरण को सुनिश्चित करने के लिए 2014 से 2.5 करोड़ से अधिक मुफ्त बिजली कनेक्शन दिए गए हैं।

जल और पर्यावरण

- जल जीवन मिशन के अंतर्गत तीन करोड़ परिवारों को पाइप वॉटर सप्लाई से जोड़ा जा चुका है।
- पेरिस समझौते को लागू करने में भारत दुनिया के अग्रणी देशों में शामिल है।

शिक्षा

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के अंतर्गत विद्यार्थियों को अपनी पसंद के विषय चुनने की स्वतंत्रता दी गई है।
- सरकार 3.2 करोड़ से अधिक विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप दे रही है।
- स्कूली शिक्षा के लिए यूनिफाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाने के लिए प्रधानमंत्री ई-विद्या के अंतर्गत दीक्षा ऑनलाइन पोर्टल को विकसित किया गया है।

महिला और बाल विकास

- जन धन योजना के अंतर्गत महिलाओं के खातों में 31,000 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए गए हैं।
- उज्ज्वला योजना के अंतर्गत महिला लाभार्थियों को 14 करोड़ गैस सिलिंडर मुफ्त दिए गए हैं।
- दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंतर्गत सात करोड़ से अधिक महिला उद्यमी लगभग 66 लाख स्वसहायता समूहों की सदस्य बनी हैं। 2014 से इन समूहों को 3.4 लाख करोड़ मूल्य के ऋण उपलब्ध कराए गए हैं।
- मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत 3.5 करोड़ बच्चों को टीके लगाए गए हैं।

अल्पसंख्यक और जनजातीय मामले

- ट्रांसजेंडर लोगों को समान अवसर प्रदान करने के लिए ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) एक्ट, 2019 लागू किया गया है।
- आदिवासी बहुल क्षेत्रों में 550 से ज्यादा एकलव्य आवासीय मॉडल स्कूलों को मंजूरी दी गई है।

टेक्नोलॉजी और अंतरिक्ष

- डिजिटल समावेश को संभव बनाने के लिए लॉन्च किए गए उमंग ऐप के जरिए 2,000 से अधिक सरकारी सेवाएं हासिल की जा सकती हैं।
- इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर (इन-स्पेस) (IN-SPACe) के गठन से अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधारों को गति मिलेगी। चंद्रयान-3, गंगायान और स्मॉल सेटेलाइट लॉन्च वेहिकल पर काम चल रहा है।

अस्वीकरणः प्रस्तुत रिपोर्ट आपके समक्ष सूचना प्रदान करने के लिए प्रस्तुत की गई है। पीआरएस लेजिसलेटिव रिसर्च (पीआरएस) के नाम उल्लेख के साथ इस रिपोर्ट का पूर्ण रूपेण या आंशिक रूप से गैर व्यावसायिक उद्देश्य के लिए पुनःप्रयोग या पुनर्वितरण किया जा सकता है। रिपोर्ट में प्रस्तुत विचार के लिए अंततः लेखक या लेखिका उत्तरदायी हैं। यद्यपि पीआरएस विश्वसनीय और व्यापक सूचना का प्रयोग करने का हर संभव प्रयास करता है किंतु पीआरएस दावा नहीं करता कि प्रस्तुत रिपोर्ट की सामग्री सही या पूर्ण है। पीआरएस एक स्वतंत्र, अलाभकारी समूह है। रिपोर्ट को इसे प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के उद्देश्यों अथवा विचारों से निरपेक्ष होकर तैयार किया गया है। यह सारांश मूल रूप से अंग्रेजी में तैयार किया गया था। हिंदी रूपांतरण में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता की स्थिति में अंग्रेजी के मूल सारांश से इसकी पुष्टि की जा सकती है।